



सच की हुंकार

संस्कार उजाला

sanskarujala@gmail.com

संस्थापक स्व० सुखराम शर्मा एवम शिवकुमार शर्मा, श्री प्रकाशवीर

सच की हुंकार



संस्थापक

श्री आर. के. शर्मा

गाजियाबाद से प्रकाशित, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, हापुड, बुलंदशहर, मथुरा आगरा, इटावा, कानपुर एवं लखनऊ से प्रसारित

वर्ष : 12 अंक : 228

रविवार 08 दिसंबर 2024, गाजियाबाद

RNI No-UPHIN / 2013 / 50466

पेज : 8 मूल्य : 2 रुपये

बांग्लादेश-भारत के बीच चल रहे तनाव के चलते बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट रोकी गई

नई दिल्ली।

शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ अत्याचार जारी है। वहीं, भारत विरोधी कदम उठाए जा रहे हैं। हालात ये हैं कि त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट को रोकना गया। बीटिंग रिट्रीट शनिवार और रविवार को आयोजित होता था। भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तनाव की के बीच अगर तला में अखूरा बॉर्डर

में बीटिंग रिट्रीट का आयोजन बंद हुआ। खबर आ रही है कि बांग्लादेश की सेना ने भारत की सीमा पर पश्चिम बंगाल के पास तुर्की निर्मित ड्रोन तैनात किए हैं। सीमा पर बांग्लादेश की सेना की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है। भारत ने शेख हसीना की अकामी लीग की सरकार गिरने के बाद बॉर्डर पर आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद से निगरानी बढ़ाई है। सूत्रों से पता चला है कि

सेना ने सीमा के करीब बेराकटर टीबी2 मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) की तैनाती की पुष्टि की है। इन ड्रोनों का संचालन बांग्लादेश की 67वीं सेना खुफिया, निगरानी और दोही मिशनों के लिए करती है। जबकि बांग्लादेश ने दावा किया कि यह तैनाती रक्षा उद्देश्यों के लिए है, भारत ने संवेदनशील क्षेत्र में ऐसे उन्नत ड्रोनों की तैनाती के रणनीतिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया है। वहीं, मुस्लिम संगठनों ने भारत के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का

आयोजन किया। इस प्रदर्शन में मुस्लिम संगठन के नेताओं ने पुलिस सुरक्षा में हुए इस प्रदर्शन में आईएसआईएस के झंडे भी लहराए गए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में भारतीयों पर हमले और उनकी हत्या करने की धमकी दी। बांग्लादेश में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि कट्टरता पर पसार रही है।



इधर, श्रीभूमि जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर हिंदू मंदिर में रिनेवेशन को रोक दिया। बांग्लादेश की सेना ने हिंदू मंदिर का रेनेवेशन का कड़ा विरोध किया था। हालांकि, बांग्लादेश की सेना ने इस संबंध में शांतिपूर्ण हल निकालने पर जोर दिया है।

दैनिक संस्कार उजाला
न्यू एंड विज्ञापन के लिए संपर्क करें

संस्कार उजाला समाचार पत्र में रिपोर्टर, एडिटर, कर्माचारियों को कानून की जरूरत है। तुरंत संपर्क करें।

महेश शर्मा
प्रबंध संपादक
सं.सं. - 8911733888

शाही इमाम बुखारी की पीएम मोदी से अपील, मुस्लिम समुदाय के साथ संवाद स्थापित करें

नई दिल्ली।

दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने नमाज के दौरान देश में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चिंता जाहिर की। इस दौरान बुखारी भावुक हो गए। उन्होंने नम आंखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने की बात की। उन्होंने कहा, हम 1947 से भी बदतर स्थिति में खड़े हैं। किसी को नहीं पता कि देश भविष्य में किस दिशा में जाएगा। बुखारी ने प्रधानमंत्री मोदी से तत्काल मुद्दे पर संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि तीन हिंदुओं और तीन मुसलमानों को बुलाकर चर्चा करें। उन्होंने कहा, आप उस कुर्सी के साथ न्याय कीजिए जिस पर आप बैठें हैं। मुसलमानों का दिल जी लीजिए। उन उद्देश्यों को रोकिए जो देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से धैर्य बनाकर रखने का अनुरोध कर कहा कि कोई भी कदम सोच-समझकर उठाएं। यह अपील उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसक झड़पों के बाद आई है। बता दें कि 19 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर मस्जिद का सर्वेक्षण हुआ। एक याचिका में दावा किया गया था कि इस स्थल पर पहले एक हरिहर मंदिर था। इसके बाद से संभल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बुखारी ने कहा, एसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) ने हमें बताया है कि दिल्ली जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार को संभल, अजमेर और अन्य जगहों पर हो रहे सर्वेक्षणों पर गंभीरता से सोचना चाहिए।

सुविचार

जिसके खिलाफ सब लोग खड़े हैं, समझ जाना वही इंसान सच्चा है।

संक्षिप्त समाचार

बांग्लादेश मामले पर मायावती का बड़ा हमला, सिर्फ मुस्लिम वोटों की खातिर चुप है कांग्रेस

अमित को बड़ी राहत, जब्त 1,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां हुईं मिलीं

महाराष्ट्र में एनटीएम नेताओं ने शापव वातावरण का बहिरकार किया, ईवीएम पर नहीं भरोसा

नेतृत्व क्षमता मजबूत हुई: पीएम मोदी

नई दिल्ली।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि निक्षय मित्र और कम समय में प्रभावी उपचार जैसी पहलों से भारत में टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जेपी नड्डा की ओर से एक्स पर की गई पोस्ट का जवाब देकर यह पोस्ट की। पीएम मोदी ने पोस्ट में कहा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने विस्तार से बताया कि कैसे भारत के टीबी उन्मूलन प्रयासों में निक्षय पोषण योजना के माध्यम से पोषण

संबंधी सहायता से परिवर्तनकारी प्रगति देखी गई है। निक्षय मित्र और कम समय में प्रभावी उपचार जैसी पहलों ने टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है, मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नड्डा ने पोस्ट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत टीबी के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। भारत में टीबी की रोकथाम के लिए कई पहल की जा रही हैं। इसमें उच्च-भार वाले जिलों में 100-दिवसीय अभियान, निक्षय पोषण योजना के माध्यम से पोषण



सहायता में वृद्धि, लागत प्रभावी निदान उपकरण जैसी पहल देश के प्रयासों को गति दे रही हैं। इन कदमों से उपचार कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और टीबी के मामलों में कमी आई है। जनभागीदारी पर जोर ने

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा में विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला

रायरंगपुर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पैतृक क्षेत्र रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के साथ ही उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

रेलवे लाइन परियोजनाएं- राष्ट्रपति मुर्मू ने बांगिरिपोसी-गोरुमहिसानी, बुरामारा-चाकुलिया और बादामपहाड़-केदुझारगढ़।

अन्य विकास कार्य- जनजातीय अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना के साथ ही द्विबंसेस हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। रायरंगपुर उप-मंडल अस्पताल के 100 बिस्तरों वाले नए भवन का निर्माण।

इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्हें हमेशा अपनी जन्मभूमि पर गर्व है और यह भूमि उनकी प्रेरणा का स्रोत रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये परियोजनाएं क्षेत्र में परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देंगी। रेलवे कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों को सुविधाजनक यात्रा और आर्थिक विकास के अवसर मिलेंगे। नया अस्पताल भवन बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इतना ही नहीं आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना क्षेत्र में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देगी।

एकलव्य मॉडल स्कूल की पहल ओडिशा में 100 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं।



इसमें से 23 विद्यालय मयूरभंज जिले में बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इन विद्यालयों से आदिवासी बच्चे समाज और देश की प्रगति में योगदान देने वाले हैं।

ओडिशा के विकास पर जोर- राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार के पूर्वोदय विजन के तहत ओडिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ी मस्जिद पर विवाद

सरकार ने इस शत्रु संपत्ति घोषित किया

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश की एक और मस्जिद को लेकर विवाद पैदा हो गया है। यह विवाद पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के नाम से जुड़ा हुआ है। यह मस्जिद उनके भाई सच्चे जाद अली खान की जमीन पर है।

इस अब सरकार के द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। इसकी जमीन के कथित रूप से वके फ संपत्ति होने का दावा किया गया। इसके बाद प्रशासन और शत्रु संपत्ति संरक्षक कार्यालय की एक टीम जांच के लिए पहुंची। यह जमीन मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के सामने करीब 0.082 हेक्टेयर में फैली हुई है। बता दें कि यह जमीन पहले रुस्तम अली के नाम पर दर्ज थी। विभाजन के बाद जब रुस्तम अली का परिवार पाकिस्तान पहुंच गया। इसके बाद भारत में मौजूद उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। बाद में इस जमीन पर कब्जा कर एक मस्जिद बना दी गई।

कौन थे लियाकत अली खान?

अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें पाकिस्तान के कायदे-मिल्लत (राष्ट्र के नेता) और शहीद-ए-मिल्लत (राष्ट्र के शहीद) के रूप में भी जाना जाता है। अली खान का जन्म 1 अक्टूबर 1895 को करनाल जिले में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की। राजनीति में उनकी शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हुई, लेकिन बाद में वे मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। लियाकत अली ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1946 में भारत में हुए चुनावों में मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता के रूप में उन्होंने पार्टी को मजबूत किया। पाकिस्तान के निर्माण के बाद वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने।

16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी में जनसभा के दौरान अली की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके हत्यारे की पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। उनकी हत्या आज भी एक रहस्य बनी हुई है।

यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात हाई कोर्ट में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

अहमदाबाद। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार को गुजरात हाई कोर्ट में राज्य के न्याय तंत्र की आधारभूत सुविधाओं को और अधिक मजबूत करने वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और विधि मंत्री ऋषिकेश पटेल उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प न्यायपालिका को मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाकर उसे समय के अनुरूप भवनों और टेक्नोलॉजी से

सुसज्जित करने का है। इस संकल्प को साकार करने की दिशा में गुजरात हाई कोर्ट में आज 133 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न हुआ है। भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजरात 1960 में अलग राज्य बना, तब नवरंगपुरा स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुई गुजरात हाई कोर्ट की यात्रा निरंतर नवीनतम सुविधाओं के साथ आगे बढ़ी है। आज गुजरात हाई कोर्ट का अद्यतन भवन सोला में स्टेट ऑफ दी अर्ट सुविधाओं के साथ कार्यरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प यह प्रयास रहा है कि न्यायालयों और उससे जुड़ी इमारतों या मकानों के निर्माण सहित

न्यायाधीशों और कोर्ट स्टाफ को अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य के प्रत्येक तहसील मुख्यालय में प्रधान सिविल जज की कोर्ट कार्यरत कर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने कानून विभाग के बजट में वित्तीय प्रावधान किए हैं। वर्ष 2021-22 में यह आवंटन 1698 करोड़ रुपये था, जिसे 2024-25 में 2586 करोड़ रुपये किया गया है। यह न्यायतंत्र की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन और सुदृढ़ मानवबल उपलब्ध कराने की राज्य सरकार

लोकतंत्र को गतिमान रखता है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुशासन का प्रत्यक्ष अनुभव हो, इसके लिए त्वरित न्याय प्राप्त होना अति आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार न्यायतंत्र और हाई कोर्ट की जरूरत के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराने को कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने कानून विभाग के बजट में वित्तीय प्रावधान किए हैं। वर्ष 2021-22 में यह आवंटन 1698 करोड़ रुपये था, जिसे 2024-25 में 2586 करोड़ रुपये किया गया है। यह न्यायतंत्र की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन और सुदृढ़ मानवबल उपलब्ध कराने की राज्य सरकार

की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने पारदर्शी और कुशल सुशासन के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी है। गुजरात हाई कोर्ट ने इस क्षेत्र में एक मिसाल के तौर पर काम किया है। गुजरात यूट्यूब पर अदालती कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राज्य की न्यायपालिका ने वचुंअल कोर्ट, डिजिटल पोर्टल, पेपरलेस ई-फाइलिंग का दृष्टिकोण भी अपनाया है। उन्होंने कहा कि आजाज जिन विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उससे न्याय प्रणाली में और अधिक तेजी आएगी।

